भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4093
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

तेल और गैस के उत्पादन तथा उनके भंडारण में वृद्धि

†4093. श्री बाबू सिंह कुशवाहा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तेल और गैस के उत्पादन तथा उनके भंडारण में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;
(ख) क्या सरकार का पर्यावरणीय संरक्षण हेतु हरित ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु किन्हीं अन्य योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है; और
(घ) क्या सरकार द्वारा भावी आवश्यकता हेतु इस संबंध में कोई नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सरकार द्वारा घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन को बढावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014।
ii. खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति, 2015।
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016।
iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017।
v. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी, 2017 की स्थापना।
vi. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिन में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।

vii. पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससी के विस्तार के लिए नीति ढांचा।

viii. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018।

ix. मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति ढांचा।

x. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के तहत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण- I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं।

xi. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को छोड़ना जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।

xii. सरकार इनलैंड और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा भी प्राप्त कर रही है और स्ट्रेटीग्राफिक कूपो की खुदाई कर रही है, ताकि बोलीदाताओं को भारतीय तलछटी आधारों का गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से परे भूमि पर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 20 भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, सरकार ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से 3 स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की कुल क्षमता के साथ सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) सुविधाएं स्थापित की हैं, जिनके नाम हैं (1) विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), (ii) मैंगलूरू (15 एमएमटी) और (ii) पादुर (2.5 एमएमटी) क्षमता।

(ख): भारत का ऊर्जा क्षेत्र हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ते फोकस के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। सरकार 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्कों की स्थापना की योजना लागू की जा रही है ताकि परियोजना डेवलपर्स को ऐसी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में सुविधा हो। सरकार ने 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और कमीशनिंग के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन का प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी)

उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करके भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।

सरकार ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) को भी अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य भारत में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का समर्थन करने के लिए जैव ऊर्जा और अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। हरित ईंधन और अन्य वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तेल और विपणन कंपनियों (आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल) को अपने खुदरा दुकानों पर कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन यानी सीएनजी/एलएनजी/इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट आदि के विपणन के लिए सुविधाएं स्थापित करना आवश्यक है।

(ग) और (घ): सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए देश भर में ईंधन/फ़ीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन, इथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस और जैव डीजल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण, रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार, ऊर्जा दक्षता, और संरक्षण, विभिन्न नीतियों और पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल हैं। किफायती परिवहन की दिशा में ऑटोमोटिव भावी विकल्प के रूप में मुक्त गैस (सीबीजी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए (एसएटीएडी) पहल भी शुरू की गई है।

सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी), संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल शामिल हैं। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) के तहत तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं और "सस्ती परिवहन के लिए सतत विकल्प' (एसएटीएटी) पहल के तहत, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के साथ संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) का विपणन किया जाता है।

ईबीपी कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2018-19 में 188.6 करोड़ लीटर से बढ़कर ईएसवाई 2023-24 में 700 करोड़ लीटर से अधिक हो गया, साथ ही मिश्रण प्रतिशत ईएसवाई 2018-19 में 5% से बढ़कर ईएसवाई 2023-24 में 14.6% हो गया। पिछले दस वर्षों के दौरान, ईबीपी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप लगभग 1,08,655 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, 185 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है और लगभग 557 लाख मीट्रिक टन शुद्ध CO_2 में कमी आई है।

तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने अपने कच्चे तेल की टोकरी में विविधता ला दी है और विभिन्न भौगोलिक स्थानों जैसे मध्य पूर्व, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि में स्थित देशों से कच्चा तेल खरीद रहे हैं।

******